POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 जुलाई, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! आज संपूर्ण विश्व पर कोरोना वायरस महामारी का संकट गहराता जा रहा है। इसका असर जन-साधारण के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था व सम्पूर्ण सरकारी व गैर-सरकारी तंत्र पर पड़ रहा है। यहीं कारण है कि हम अप्रेल माह के अंक के बाद सीधे जुलाई के अंक के मार्फत रूबरू हो रहे हैं, जिसमें हमने मई और जून माह का भी समावेश करने का प्रयास किया है।

जहाँ विश्व में लाखों लोग इस महामारी के चलते अपने प्राण गवां रहे हैं, वहीं विश्व अर्थव्यवस्था पर इससे कई दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। भारत भी इनसे अछूता नहीं है।

कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चौथी बार लॉकडाउन बढाने की घोषणा के साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के लिए 20 लाख करोड़ रूपए के पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज देश की अर्थव्यवस्था का दस फीसदी है।

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई है। हमें अपने इस संकल्प को पूरा करना है। थकना, हारना, टूटना-बिखरना हमें मंजूर नहीं है। हमें सतर्क रहते हुए जंग के सभी नियम मानते हुए, बचना भी है और आगे बढना भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह आपदा भारत के लिए अवसर लेकर आई है। 21वीं सदी भारत की होगी।

इस पैकेज में व्यापार, उद्योग, किसानों, रोज कमाने-खाने वाले लोगों, गरीबों, छोटे-मंझोले कारोबारियों का खास ध्यान रखा गया है। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादों की गुणवत्ता और नई-नई तकनीक अपनाते हुए, नई खोजों, कौशल विकास और रक्षा क्षेत्र के कई उत्पादनों में श्रेष्ठता का निर्माण करते हुए कई सपनों को साकार किया जा सकेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एम.एस.एम.ई.) उद्योगों को बिना किसी गारंटी के कर्ज की सुविधा देना तथा उत्पाद खरीदने के लिए नियम बदलना अच्छे कदम हैं। इससे उद्योग सुविधाएं प्राप्त कर विकास कर सकेंगे। प्रवासी मजदूरों, सीमांत किसानों को राहत, ऋण और मदद की घोषणाएँ प्रशंसनीय है।

अमूमन रूप से देखा गया है कि सरकारी घोषणाएँ समय पर धरातल पर नहीं उतर पाती, इसके लिए नौकरशाहों पर नियंत्रण और निगरानी आवश्यक है। इससे जन आकांक्षाएँ कसौटी पर खरी उतर पाएगी।

खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं में कामकाज प्रारम्भ

राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में रियायत के बाद राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी लगभग पांच सौ संस्थाओं ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

इन संस्थाओं की इकाईयों में मिट्टी के बर्तन, मसाला, पापड़, मंगोड़ी, आचार, हस्तशिल्प, आटा पिसाई जैसे काम शुरू हो गए हैं, जिनमें 2700 श्रमिकों को कामकाज मिला है। खादी संस्थाओं के खुलने से 852 कातिनों को रोजगार मिला है।

प्रदेश में विकसित होंगे 10 हजार तालाब

मनरेगा के तहत राजस्थान के गांवों में 10 हजार से अधिक आदर्श तालाब विकसित करने की योजना सरकार ने बनाई है। इन कार्यों के लिए मंजूरी भी जारी हो गई है। कोरोना महामारी के दौर में लगातार बढ रहे श्रमिकों के दम पर इस मानसून में पानी की किल्लत वाली मरूधरा के लिए मनरेगा वरदान साबित हो सकती है। राज्य की एक गांव एक काम योजना के तहत केन्द्र सरकार ने भी मनरेगा में इस मानसून में, विशेष तौर पर जल संरक्षण कार्यों पर जोर देने के निर्देश राज्य को दिए हैं।

राज्य की योजना में शेष तीन कार्यों में हर राजस्व गांव में खेल मैदान, चारागाह विकास व शमशान व कब्रिस्तान का विकास शामिल है। प्रदेश में करीब 40 हजार राजस्व गांव हैं, इनमें से 10 हजार के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। केन्द्र की एडवाइजरी में जल संरक्षण के लिए कराये जाने वाले कार्यो को बताया है। इनमें जलस्त्रोतों की मरम्मत और वृद्धि, वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण, प्राचीन जल स्त्रोतों का पुनरूद्धार जैसे कार्य शामिल हैं।

टिड्डियों को मारने के लिए खरीदेंगे 100 अग्निशमन वाहन

राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष से अग्निशमन वाहनों की खरीद के निर्देश दिए। इसके लिए जिला कलेक्टरों को 1.47 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं। इससे अपने क्षेत्रों में कलेक्टर टिड्डियों पर छिड़काव कर तत्काल रोकथाम की व्यवस्था कर सकेंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस पर जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा

कट्स द्वारा 5 जून, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरणविद्ध एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थें।

वक्ताओं में श्री प्रदीप एस. महता, महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल, अनुभा प्रसाद, राष्ट्रीय समन्वयक, पेज, यू.एन.ई.पी., मारिया रिडलूंड, वरिष्ठ नीति सलाहकार, स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन, स्टॉकहोम, नाओमी स्कॉटमर्न्स, सतत् उपभोग प्रबन्धक, कन्ज्यूमर इंटरनेशनल, लंदन और बालाकृष्णा पिसुपथी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। सभी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के परिणामस्वरूप दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा प्रभाव पडा है।

ऐसी परिस्थिति में जैव विविधता संरक्षण भी एक चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। जैव विविधता संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा। ईको लेबल वाले उत्पादों को बढावा देना होगा, साथ ही हमें सतत् उपभोग की संस्कृति की ओर बढना होगा। इस वेबिनार में देश के कई राज्यों और विदेशों में कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किये।

कामधेनू डेयरी योजना शुरू

राज्य के पशुपालन विभाग ने देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढावा देने के लिए कामधेनू डेयरी योजना प्रारम्भ की है। इसमें अधिकतम एक इकाई 36.68 लाख की होगी, जिसमें प्रोजेक्ट लागत का 30 फीसदी सरकार

खर्च करेगी और 10 फीसदी डेयरी स्थापित करने वाले उद्यमी को वहन करनी होगी। 60 फीसदी राशि बैंक की ओर से ऋण के रूप में दी जायेगी।

प्रदेश में खाद्य जिंसों का पर्याप्त भंडार

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबुलाल गुप्ता का कहना है कि प्रदेश में खाद्य जिंसों और जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बावजूद आटा, दाल एवं तेल की राज्य में कमी नहीं है। इसको लेकर किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

वर्तमान में राज्य की आटा मिलों में पर्याप्त उत्पादन हो रहा है तथा दाल मिलों व दलहन मिलों को नेफैड के माध्यम से स्टॉक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा मिलों द्वारा किसानों से सीधे खरीद करने के भी राज्य सरकार ने जरूरी आदेश दिये हैं।

किसान दूसरे राज्यों में भी बेच सकेंगे फसल

केन्द्र सरकार ने मंडी कानून में बदलाव कर किसानों को अपनी फसल को नोटिफाइड बाजार समिति के बाहर और दूसरे राज्यों में भी बेचने की छूट दे दी है। इसी तरह अब किसानों को सीधे निर्यातकों और बड़े विक्रेताओं से एग्रीमेन्ट करने की छूट भी होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई

केबिनेट की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। अकाल एवं आपातकाल में कृषि उपज की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

पेयजल के लिए 65 करोड़ स्वीकृत

राज्य में पेयजल किल्लत के समाधान के लिए जलदाय विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 65 करोड़ 12 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की है।

जलदाय विभाग की नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष व जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला ने बताया कि पेयजल की संभावित मांग को देखते हुए यह राशि स्वीकृत की गई है। शहरी क्षेत्रों के लिए 24 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 41 करोड़ 12 लाख की स्वीकृति जारी की है।

पशु अनुसंधान केन्द्र ओर्गेनिक गेहूँ बेचेगे

गायों के दूध से आमदनी करने वाला जैसलमेर जिले में स्थित चांधन अनुसंधान केन्द्र अब ओर्गेनिक खाद्य उत्पादों से भी आय प्राप्त करेगा। उत्तम थारपारकर नस्ल के लिए पहचान बना चुके इस केन्द्र ने अब ओर्गेनिक गेहूँ का उत्पादन कर उसे बेचने की प्रक्रिया शुरू की है।

पशु अनुसंधान केन्द्र के प्रभारी डॉ. राहुल पाल ने बताया कि केन्द्र में गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी गेहूँ उत्पादन किया गया है। ये गेहूँ पूरी तरह से ओर्गेनिक हैं। इस वर्ष लगभग 40 क्विंटल गेहूँ होने का अनुमान है।

विषाक्त टमाटर खाने से बच्चों की मौत

जयपुर जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के चौंप गांव के बावरियों की ढाणी में टमाटर खाने से किसान हजारीलाल के बेटा-बेटी की मौत हो गई तथा दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन सभी बच्चों ने खेत से टमाटर तोड़कर खाए थे जिन पर एक दिन पहले ही कीटनाशक का छिड़काव किया गया था।

नियमों का पालन करेंगे तभी कोरोना हारेगा

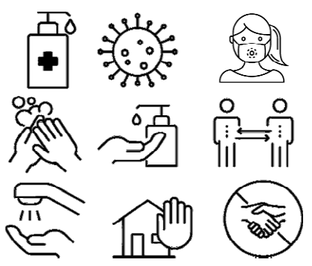

कोरोना बीमारी से डरे नहीं, उसे छिपाए नहीं। यह बात पाली निवासी माधोसिंह कह रहे हैं। चिकित्सक से परामर्श एवं इलाज लें तथा कोरोना महामारी में सरकारी आदेशों का पूरी तरह पालना करें। माधोसिंह, जो स्वयं कोरोना की चपेट में आ गए थे, ने बताया कि मुझे कोरोना पोजिटिव होने की जानकारी मिली तो मैं तनाव में कतई नहीं आया। मेरे हौसले के आगे कोरोना हार गया और मैं पन्द्रह दिन बाद घर लौट आया।

चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ का मैं तहेदिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा मेरी फिक्र की। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मैं भजन सुनता था व ईश्वर की अराधना करता था। योग-प्राणायाम भी नियमित रूप से करता था। इसके अलावा मैंने स्वयं को मजबूत रखा। कोरोना महामारी से बहुत से मरीज ठीक होकर घर आ गये हैं।

कोरोना में आत्मनिर्भर बनी महिलाएं

सिरोही जिले के पिण्डवाडा और आबू रोड़ की आदिवासी महिलाएं खुद के बनाए 36 किचन गार्डन से 400 परिवारों तक सब्जियां पहुंचाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। कोरोना की इस महामारी के बीच किचन गार्डन से महिलाएं 10 से 12 हजार रूपये महिना कमा रही हैं।

इसके अलावा, इस क्षेत्र में यहां आदिवासी परिवार का हर दसवां घर भी बकरी एवं मुर्गीपालन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इससे भी एक परिवार को प्रति माह 2 से 15 हजार रूपये प्रति माह की अतिरिक्त आय हो रही है। ऐसे समय में यहां के पुरूषों को कोरोना के संकट के समय में रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ रहा है। ये महिलाएं गृह वाटिका लगाकर हरी सब्जियां बेचकर अच्छी आमदनी ले रही हैं।

गांव में न फैले कोरोना, पेड़ों पर बसेरा

जोधपुर से आने के बाद स्वयं को परिवार से दूर रखने के लिए सीकर जिले के गांव दुल्हेपुरा निवासी पवन कुमार कोटिया ने पेड़ पर मचान बनाकर क्वारंटीन कर लिया है।

पवन ने शीशम के पेड़ पर करीब 15-18 फीट की ऊंचाई पर चारपाई बांधकर मचान बना लिया। पवन ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोरोना का संक्रमण गांव में ना फैले।

कोरोना के लक्षण स्वाइन फ्लू जैसे

राज्य के चिकित्सा विभाग ने कहा है कि कोरोना जांच से बचने के लिए खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश आदि से प्रभावित कई लोग डॉक्टर से परामर्श किए बिना सीधे दुकानों से दवाईयां ले रहे हैं।

ऐसे लक्षणों वाले मरीज के संबंध में चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि कोरोना और स्वाइन फ्लू के लक्षण समान है। लोग मनमर्जी से अपने स्तर पर दवा न लें और दवा विक्रेता भी दवा न दें। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाए।

लॉकडाउन नहीं तो, 29 लाख पोजिटिव

केन्द्र सरकार ने कहा है कि यदि सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लागू न किया होता तो अब तक देश में 29 लाख से भी ज्यादा पोजिटिव मामले होते तथा 78 हजार की मौत हो जाती।

लॉकडाउन लगाने के कारण ऐसा नहीं हुआ। इससे संक्रमण दर 22.6% से घटकर 5% तथा मृत्यु दर 48% से घटकर 5.5% हो गई।

राष्ट्रीय टैरिफ नीति में संशोधन

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में संशोधित विद्युत अधिनियम, 2020 पर आम जनता और सामाजिक संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किये थे। विद्युत मंत्रालय विद्युत सुधारों के तहत राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2006 में संशोधन पर विचार कर रहा है। इस संशोधित टैरिफ नीति को निरीक्षण कर रहे मंत्री समूह ने अपनी मंजूरी दे दी है। संशोधित नीति के अनुसार विद्युत क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस नीति के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं के बीच टैरिफ में अंतर को खत्म किया जायेगा। इसके अलावा डिस्कॉम्स को 24X7 घंटे बिजली देने के मानकों, हद से ज्यादा विद्युत कटौती और 15 फीसदी से अधिक छीजत का उपभोक्ताओं पर भार नहीं डालने का सुझाव दिया गया है।

संशोधित नीति के अनुसार उपभोक्ता वर्गों की संख्या जो पचास से साठ के करीब हैं, को घटाकर वोल्टेज के आधार पर छह करने का भी प्रस्ताव है। आगे से उपभोक्ताओं को किसी भी तरीके की सब्सिडी डी.बी.टी. द्वारा दी जायेगी। हालांकि, इन प्रस्तावों से मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बल मिलेगा, कई राज्यों ने इन सुधारों के बारे में असंतोष व्यक्त किया है। राज्यों के अनुसार उपभोक्ताओं की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इन सुधारों के जमीनी स्तर पर कार्यन्वयन में काफी चुनौतियां आएगी। उपभोक्ता और स्थानीय सामाजिक संगठन इन प्रस्तावों पर अपने विचार कट्स इंटरनेशनल के कार्यालय में भेज सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर